

मुख्य समाचार

- बजट में आम आदमी को बड़ी राहत, आयकर दरों में हुई कटौती, झारखण्ड समेत पांच राज्यों के समग्र विकास के लिए पूर्वोदय योजना लागू करने की घोषणा।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा—सभी वर्ग को सशक्त करेगा यह बजट।
- सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में सुनाया फैसला, दोबारा परीक्षा कराने की मांग ठुकरायी।
- मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा—सभी जिलों में कुष्ट रोगियों के लिए बनाये जायेंगे फ्लैट।

और

- राज्य में मानसून फिर सक्रिय, रांची और कोल्हान समेत कई क्षेत्रों में सुबह से हो रही है बारिश।

केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामण ने आज लोकसभा में वर्ष 2024–25 का आम बजट पेश किया। यह नरेन्द्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है। वित्तमंत्री ने व्यक्तिगत आयकर दरों के संबंध में नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वालों के लिए दो घोषणाएं कीं। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्षन यानी मानक कटौती को 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 75 हजार रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है। पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15 हजार रुपए से बढ़ाकर 25 हजार रुपए करने का प्रस्ताव है। नई कर व्यवस्था में कर दर संरचना में भी संशोधन किया गया है। तीन लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा।

बजट में झारखण्ड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्रप्रदेश को शामिल करते हुए देश के पूर्वी क्षेत्र के चहुंमछी विकास के लिए पूर्वोदय नामक योजना लागू करने की घोषणा की गयी है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट सभी वर्ग को शक्ति प्रदान करने वाला है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नया स्केल मिलेगा। इससे जनजातीय समुदाय, युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी।

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय बजट 2024–25 में रेलवे के लिए आवंटन को ऐतिहासिक बताया है। नई दिल्ली में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि रेलवे के लिए बजट में अब तक का सबसे अधिक दो लाख 62 हजार 200 करोड़

रुपये का आवंटन किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे रेलवे की योजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। श्री वैष्णन ने कहा कि इस बजट में रोजगार सुजन पर विशेष फोकस किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने नीट—यूजी 2024 की परीक्षा रद्द करने और इसे दोबारा आयोजित करने का आदेश देने से आज इन्कार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश डीवार्ड चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इस संबंध में दायर कई याचिकाओं की सुनवाई के बाद आज यह फैसला सुनाया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि यह साबित करने का कोई प्रमाण नहीं है कि प्रश्नपत्र लीक हुआ था और परीक्षा के संचालन में प्रणालीगत खामियां थीं जिससे पूरी परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई। न्यायालय ने यह भी कहा कि दोबारा परीक्षा कराने के गंभीर परिणाम होंगे। ऐसा करने से 23 लाख से अधिक छात्र प्रभावित होंगे और शैक्षणिक कार्यक्रम बाधित होगा। आने वाले वर्षों में इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार सभी जिलों में कुष्ठ रोगियों के लिए फ्लैट का निर्माण करायेगी। रांची के धुर्वा में निर्मित कुष्ठ कॉलोनी का उदघाटन करते हुए श्री सोरेन ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार सभी वर्गों के प्रति संवेदनशील है।

बाद में श्री सोरेन ने विभिन्न विभागों के लिए चयनित तकनीकी कर्मियों के बीच नियुक्ति पत्र का भी वितरण किया।

राज्य भर में मतदाताओं के लिए 25 जुलाई से नाम जांचो अभियान चलाया जायेगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज रांची में पत्रकारों को बताया कि इस दिन सभी जिलों में मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची की प्रति और प्रपत्र छह, सात तथा आठ के साथ बीएलओ उपस्थित रहेंगे। इस दौरान मतदाता अपने नाम की जांच करने के बाद अपनी सेल्फी सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर पोस्ट कर सकते हैं।

राज्य में मॉनसून फिर सक्रिय हो गया है। इसका असर राजधानी सहित कई जिलों में दिख रहा है। रांची में आज सुबह से ही रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान में बताया है कि 23 जुलाई को रांची और आसपास के साथ ही कोल्हान, उत्तरपूर्वी और दक्षिण पूर्वी भाग में भारी बारिश हो सकती है।

सिमडेगा जिले में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन योजना के तहत खेल प्रतिभा खोज कार्यक्रम शुरू हो गया है।